International Journal of Emerging Voices in Education
©PIJMS | Volume 1 | Issue 4 | December 2025 | ISSN: 3107-958X (Online)
Available online at: https://ijeve.com/
DOI: https://doi.org/10.59828/ijeve.v1i4.21

भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा: वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और समाधान

डॉ भावना सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला, स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, मेरठ

Email: bhavnasinghsmp@gmail.com

Received: 09 December 2025 | **Accepted:** 25 December 2025 | **Published:** 30 December 2025

सार (Abstract)

समावेशी शिक्षा आधुनिक शैक्षणिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सभी बच्चों को, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह शोध आलेख भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति, इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और संभावित समाधानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा के विभिन्न आयामों की गहन समीक्षा की गई है।

मुख्य शब्द: *समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शैक्षणिक समानता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सामाजिक न्याय*

1. प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और यह प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21-ए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। हालांकि, लंबे समय तक शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को उचित शैक्षणिक अवसर नहीं मिल पाए थे (सिन्हा, 2018)।

समावेशी शिक्षा इस अंतर को पाटने का एक प्रगतिशील दृष्टिकोण है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक शैक्षणिक दर्शन है जो विविधता का सम्मान करता है और प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय क्षमताओं और आवश्यकताओं को पहचानता है (अहूजा और इब्राहिम, 2006)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जी रही है। भारत में यह संख्या लगभग 2.68 करोड़ है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है (जनगणना 2011)। इन बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना न केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न है, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी आवश्यक है।

2. समावेशी शिक्षा: अवधारणा और सैद्धांतिक आधार

2.1 समावेशी शिक्षा की परिभाषा

समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियाँ कुछ भी हों, एक साथ सीखते हैं। यूनेस्को के अनुसार, समावेशी शिक्षा विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया है और सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूलित करती है (UNESCO, 2009)।

समावेशी शिक्षा तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: उपस्थिति (सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन), भागीदारी (सभी बच्चों की सक्रिय शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता), और उपलब्धि (सभी बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर) (जुल्का और चड्ढा, 2006)।

This is an open access article under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में समावेशी शिक्षा की यात्रा लंबी रही है। प्रारंभ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पृथक विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1974 में समन्वित शिक्षा योजना (IEDC) की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना था। 1987 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया (शर्मा, 2015)। 1995 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम और 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) महत्वपूर्ण कानूनी मील के पत्थर थे। 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ने समावेशी शिक्षा को और मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया (गोयल, 2021)।

2.3 सैद्धांतिक आधार

समावेशी शिक्षा कई शैक्षणिक सिद्धांतों पर आधारित है। लेव वायगोत्स्की का सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है और विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अंतःक्रिया सभी बच्चों के विकास को बढ़ावा देती है। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह स्थापित करता है कि बुद्धि एकल नहीं बल्कि बहुआयामी है, और प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है (वर्मा, 2019)।

जॉन डूई का प्रगतिशील शिक्षा दर्शन भी समावेशी शिक्षा को समर्थन देता है, जो बच्चे-केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को महत्व देता है। भारतीय संदर्भ में, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा और रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन भी समावेशिता के विचार से संबद्ध हैं (पांडे, 2017)।

3. भारत में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति

3.1 नीतिगत ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है। नीति में कहा गया है कि शैक्षणिक प्रणाली को सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी बनाया जाना चाहिए। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) तैयार करने, सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है (MHRD, 2020)। समग्र शिक्षा अभियान 2018 ने पूर्व की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया और समावेशी शिक्षा के लिए विशेष बजट आवंटन का प्रावधान किया। इसके तहत विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई है (राव और मुखर्जी, 2019)।

3.2 क्रियान्वयन की स्थिति

विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में मिश्रित परिणाम हैं। UDISE+ 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 22 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भारत के विद्यालयों में नामांकित हैं। हालांकि यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं (मित्रा, 2020)।

शहरी क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। निजी विद्यालयों में भी सरकारी विद्यालयों की तुलना में समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं, हालांकि सभी निजी विद्यालय इस दिशा में समान रूप से प्रतिबद्ध नहीं हैं (सक्सेना और मिश्रा, 2018)।

3.3 सफलता की कहानियाँ

कुछ राज्यों और संस्थानों ने समावेशी शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम विकसित किए हैं। दिल्ली के कुछ विद्यालयों में विशेष संसाधन कक्षों की स्थापना और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है (चतुर्वेदी, 2021)।

गैर-सरकारी संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाटा ट्रस्ट, अक्षय पात्र फाउंडेशन और प्रथम जैसे संगठन समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं (वर्मा और राजपूत, 2020)।

4. समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ

4.1 बुनियादी ढांचे की कमी

भारत के अधिकांश विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा नहीं है। रैंप, विशेष शौचालय, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरणों की कमी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी चिंताजनक है जहाँ बुनियादी शैक्षणिक सुविधाएँ भी पर्याप्त नहीं हैं (जोशी, 2019)।

NCERT के एक अध्ययन के अनुसार, केवल 15 प्रतिशत विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है। शहरी-ग्रामीण अंतर भी स्पष्ट है, जहाँ शहरी विद्यालयों में 25 प्रतिशत जबकि ग्रामीण विद्यालयों में केवल 10 प्रतिशत में ही उचित सुविधाएँ हैं (NCERT, 2019)।

4.2 शिक्षकों की तैयारी और प्रशिक्षण

समावेशी शिक्षा की सफलता में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, अधिकांश शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता। एक अध्ययन के अनुसार, केवल 30 प्रतिशत शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है (मल्होत्रा, 2018)।

शिक्षकों में आत्मविश्वास की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई शिक्षक यह महसूस करते हैं कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इससे वे या तो इन बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें अलग-थलग रखते हैं, जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के विपरीत है (सिंह और कौर, 2020)।

4.3 सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ

भारतीय समाज में विकलांगता के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण अक्सर नकारात्मक रहा है। कई परिवार अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते क्योंकि वे मानते हैं कि इन बच्चों को शिक्षा से कोई लाभ नहीं होगा। सामाजिक कलंक और भेदभाव भी इन बच्चों की शिक्षा में बाधक हैं (गुप्ता, 2017)।

विद्यालयों में भी अन्य बच्चों और उनके अभिभावकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति नकारात्मक रवैया देखा जाता है। कुछ अभिभावक यह चिंता व्यक्त करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उपस्थिति से कक्षा की गति धीमी हो जाएगी और उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी (कपूर, 2019)।

4.4 आर्थिक बाधाएँ

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। विशेष उपकरण, प्रशिक्षित कर्मचारी, बुनियादी ढांचे में सुधार और व्यक्तिगत सहायता सेवाओं के लिए अतिरिक्त बजट चाहिए। हालांकि, अधिकांश विद्यालयों, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में, पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं (नायर, 2018)।

गरीब परिवारों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। चिकित्सा व्यय, विशेष उपकरण और परिवहन की लागत उनके लिए वहन करना कठिन हो जाता है। यद्यपि सरकारी योजनाओं में कुछ वित्तीय सहायता का प्रावधान है, लेकिन यह अपर्याप्त है और कई बार इसका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता (त्रिपाठी, 2020)।

4.5 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की समस्याएँ

वर्तमान पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली मुख्यतः सामान्य बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लचीली पाठ्यक्रम और वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों की आवश्यकता है, जो अभी बहुत सीमित है। एक ही परीक्षा प्रणाली सभी बच्चों पर लागू करना समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है (भट्टाचार्य, 2021)।

पाठ्य सामग्री भी अक्सर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलभ नहीं होती। ब्रेल लिपि में पुस्तकें, ऑडियो पुस्तकें, सरल भाषा में सामग्री और दृश्य-श्रव्य सामग्री की कमी है। डिजिटल सामग्री भी अक्सर सुलभता मानकों के अनुरूप नहीं होती (शर्मा और पटेल, 2019)।

5. समावेशी शिक्षा के लिए रणनीतियाँ और समाधान

5.1 बुनियादी ढांचे में सुधार

सभी विद्यालयों को सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए, जिससे वे सभी बच्चों के लिए सुलभ हों। इसमें रैंप, लिफ्ट, विशेष शौचालय, उपयुक्त फर्नीचर और विशेष कक्षों का निर्माण शामिल है। सरकार को इस दिशा में पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए और निर्माण मानकों को कड़ाई से लागू करना चाहिए (मेहता, 2020)।

सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। श्रवण यंत्र, विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टच स्क्रीन, वॉयस टू टेक्स्ट एप्लिकेशन और अन्य तकनीकी उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सरकार को इन उपकरणों की खरीद और रखरखाव के लिए विशेष फंड की व्यवस्था करनी चाहिए (दास, 2021)।

5.2 शिक्षक प्रशिक्षण और विकास

सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। B.Ed और D.El.Ed पाठ्यक्रमों में विशेष शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके साथ काम करने की तकनीकों पर व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सेवारत शिक्षकों के लिए नियमित पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए (अग्रवाल, 2019)।

प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षकों या संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो सामान्य शिक्षकों को सहायता प्रदान कर सकें। इन विशेष शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षा योजना तैयार करने, सहायक सामग्री विकसित करने और शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने में विशेषज्ञता होनी चाहिए (रेड्डी, 2018)।

5.3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में लचीलापन

पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सार्वभौमिक शिक्षण डिजाइन (Universal Design for Learning) के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए, जो विविध शिक्षार्थियों के लिए अनेक प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और संलग्नता के तरीके प्रदान करता है (खान, 2020)।

मूल्यांकन प्रणाली में भी लचीलापन होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय, वैकल्पिक परीक्षा प्रारूप (जैसे मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन), सहायक उपकरणों का उपयोग और लेखक की सहायता जैसी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की वास्तविक सीखने की क्षमता को मापना होना चाहिए, न कि उनकी विकलांगता को (मिश्रा, 2019)।

5.4 सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता

समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए पूरे समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। अभिभावकों, स्थानीय समुदाय के सदस्यों और नागरिक समाज संगठनों को समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान, कार्यशालाएँ और सामुदायिक बैठकें इस दिशा में सहायक हो सकती हैं (पाटिल, 2020)।

मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक कहानियों और रोल मॉडल को प्रचारित करके विकलांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सफलता की कहानियाँ युवाओं को प्रेरित कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं (वर्मा, 2021)।

5.5 प्रौद्योगिकी का उपयोग

डिजिटल तकनीक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म, शैक्षणिक एप्लिकेशन और डिजिटल संसाधन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने को अधिक सुलभ और रोचक बना सकते हैं। स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और अन्य सुलभता सुविधाओं से युक्त डिजिटल सामग्री विकसित की जानी चाहिए (जैन, 2020)। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाने और प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रैक करने में किया जा सकता है। एडाप्टिव लर्निंग सिस्टम हर बच्चे की गति और शैली के अनुसार सामग्री को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि तकनीक मानवीय संपर्क का स्थान न ले, बल्कि उसे पूरक बनाए (चौधरी, 2021)।

5.6 नीतिगत और कानूनी सुदृढ़ीकरण

समावेशी शिक्षा से संबंधित कानूनों और नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। विद्यालयों द्वारा समावेशी शिक्षा के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता है। जो विद्यालय नियमों का पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए (बनर्जी, 2019)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना और समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को समावेशी शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए और इसके उपयोग की पारदर्शी रिपोर्टिंग होनी चाहिए (पाटिल, 2020)।

6. अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और सबक

6.1 विकसित देशों के मॉडल

संयुक्त राज्य अमेरिका में Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) के तहत सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क और उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (IEP) तैयार किया जाता है जिसमें अभिभावक, शिक्षक और विशेषज्ञ मिलकर भाग लेते हैं (Smith & Tyler, 2010)।

यूनाइटेड किंगडम में विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएँ और विकलांगता (SEND) कोड व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्थानीय प्राधिकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, मूल्यांकन और सहायता के लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के बीच समन्वय पर बल दिया जाता है (Norwich, 2014)।

फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली समावेशिता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ "सभी के लिए एक विद्यालय" का सिद्धांत है और लगभग सभी बच्चे, उनकी आवश्यकताएँ चाहे कुछ भी हों, नियमित विद्यालयों में पढ़ते हैं। शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक विद्यालय में विशेष सहायता प्रणाली होती है (Kivirauma et al., 2006)।

6.2 विकासशील देशों के अनुभव

दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के बाद समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी। White Paper 6 on Special Needs Education ने समावेशी शिक्षा प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि संसाधनों की कमी और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण पूर्ण क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आई हैं (Engelbrecht et al., 2006)।

ब्राजील ने भी समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2008 की राष्ट्रीय नीति ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित विद्यालयों में शिक्षा को प्राथमिकता दी। मल्टीफंक्शनल रिसोर्स रूम की अवधारणा विकसित की गई जहाँ विशेष सहायता प्रदान की जाती है (Mendes, 2010)।

भारत इन अनुभवों से सीख सकता है, विशेषकर संसाधनों के प्रभावी उपयोग, बहु-क्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में।

7. अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक भारतीय अनुसंधान की आवश्यकता है। वर्तमान में अधिकांश शोध पश्चिमी संदर्भ में किए गए हैं और भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में उनकी प्रासंगिकता सीमित हो सकती है। भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता, शिक्षकों की तैयारी, सामाजिक दृष्टिकोण और नीतिगत क्रियान्वयन पर अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए (राव, 2017)। नवाचारी प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पीयर लर्निंग, सहयोगी शिक्षण, खेल-आधारित शिक्षा और कला समेकित शिक्षा जैसी विधियाँ समावेशी कक्षाओं में प्रभावी हो सकती हैं। विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों द्वारा किए जा रहे सफल प्रयोगों का दस्तावेजीकरण और प्रसार किया जाना चाहिए ताकि अन्य भी उनसे सीख सकें (कुमार, 2020)।

8. माता-पिता और परिवार की भूमिका

समावेशी शिक्षा में माता-पिता और परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बच्चे के प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं। अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। उन्हें अपने बच्चे के शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना बनाने, निर्णय लेने और मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए (गुप्ता और सिंघल, 2018)।

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें उन्हें घर पर बच्चों की शैक्षणिक और विकासात्मक गतिविधियों में सहायता करने के तरीके सिखाए जाएँ। अभिभावक सहायता समूह बनाए जा सकते हैं जहाँ वे अनुभव साझा कर सकें और एक-दूसरे को भावनात्मक और व्यावहारिक समर्थन दे सकें (शर्मा, 2019)।

9. निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षणिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों का मूलभूत प्रश्न है। भारत ने समावेशी शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। नीतियाँ और कानून तो बन गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी चुनौती बना हुआ है।

समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में लचीलापन, सामुदायिक भागीदारी और पर्याप्त वित्तीय संसाधन शामिल हों। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज को इसमें भागीदार बनना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के लिए एक मजबूत रूपरेखा प्रदान की है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसे जमीनी स्तर पर ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए। प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी परिस्थितियाँ कुछ भी हों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा इस अधिकार को साकार करने का माध्यम है।

एक समावेशी समाज का निर्माण समावेशी शिक्षा से ही संभव है। जब बच्चे विविधता के बीच बड़े होते हैं, जब वे सीखते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और सबका योगदान मूल्यवान है, तो वे अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। यही समावेशी शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है - एक ऐसे समाज का निर्माण जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और भागीदारी मिले।

संदर्भ सूची

[1]. अग्रवाल, ए. (2019). शिक्षक प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षा: आवश्यकता और चुनौतियाँ. *भारतीय शिक्षा जर्नल*, 45(2), 112-128.

[2]. अहूजा, ए., और इब्राहिम, F. (2006). समावेशी शिक्षा की अवधारणा और भारतीय परिप्रेक्ष्य. *शैक्षिक अध्ययन*, 32(1), 45-60.

[3]. गुप्ता, एस. (2017). भारतीय समाज में विकलांगता: सामाजिक दृष्टिकोण और चुनौतियाँ. *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*, 28(3), 78-95.

[4]. गुप्ता, आर., और सिंघल, पी. (2018). समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका. *पारिवारिक शिक्षा जर्नल*, 15(4), 201-218.

[5]. गोयल, एन. (2021). समावेशी शिक्षा का कानूनी ढांचा: भारतीय संदर्भ. *शिक्षा और कानून समीक्षा*, 12(1), 34-52.

[6]. चतुर्वेदी, वी. (2021). दिल्ली के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा: एक केस स्टडी. *नगरीय शिक्षा अध्ययन*, 18(2), 145-162.

[7]. चौधरी, एस. (2021). समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग. *शैक्षिक तकनीक जर्नल*, 9(3), 88-105.

[8]. जनगणना (2011). भारत में विकलांग व्यक्ति: 2011 की जनगणना. भारत सरकार.

[9]. जैन, पी. (2020). डिजिटल समावेशन: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी. *डिजिटल शिक्षा समीक्षा*, 7(1), 56-73.

[10]. जोशी, आर. (2019). ग्रामीण भारत में समावेशी शिक्षा: बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ. *ग्रामीण विकास जर्नल*, 38(4), 234-251.

[11]. जुल्का, ए., और चड्ढा, N. (2006). भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे: समावेशन के मुद्दे. *विशेष शिक्षा अध्ययन*, 14(2), 67-84.

[12]. त्रिपाठी, एस. (2020). समावेशी शिक्षा की आर्थिक चुनौतियाँ: गरीब परिवारों का दृष्टिकोण. *शैक्षिक अर्थशास्त्र*, 25(3), 189-207.

[13]. दास, के. (2021). सहायक प्रौद्योगिकी और समावेशी शिक्षा. *भारतीय पुनर्वास जर्नल*, 32(1), 45-62.

[14]. नायर, एम. (2018). समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन: एक विश्लेषण. *शिक्षा वित्त और नीति*, 13(2), 98-115.

[15]. पांडे, आर. (2017). भारतीय शिक्षा दर्शन और समावेशिता. *दार्शनिक अध्ययन*, 22(4), 156-173.

[16]. पाटिल, एस. (2020). समावेशी शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी. *सामुदायिक विकास जर्नल*, 16(3), 123-140.

[17]. बनर्जी, ए. (2019). समावेशी शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन: चुनौतियाँ और समाधान. *नीति अध्ययन समीक्षा*, 11(2), 78-96.

[18]. भट्टाचार्य, पी. (2021). समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन की समस्याएँ. *शैक्षिक मापन जर्नल*, 19(1), 34-51.

[19]. मल्होत्रा, एस. (2018). शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति तैयारी. *शिक्षक शिक्षा जर्नल*, 27(3), 145-162.

[20]. मिश्रा, आर. (2019). लचीला मूल्यांकन: समावेशी शिक्षा की आवश्यकता. *मूल्यांकन अध्ययन*, 14(4), 201-218.

[21]. मित्रा, एस. (2020). भारत में समावेशी शिक्षा की स्थिति: UDISE डेटा विश्लेषण. *शैक्षिक आंकड़े और अनुसंधान*, 8(1), 56-74.

[22]. मेहता, वी. (2020). सार्वभौमिक डिजाइन और विद्यालय बुनियादी ढांचा. *शैक्षिक वास्तुकला*, 5(2), 89-106.

[23]. राव, एस. (2017). भारत में समावेशी शिक्षा अनुसंधान: स्थिति और भविष्य की दिशा. *शैक्षिक अनुसंधान समीक्षा*, 24(3), 167-185.

[24]. राव, पी., और मुखर्जी, डी. (2019). समग्र शिक्षा अभियान और समावेशिता. *शैक्षिक नीति विश्लेषण*, 17(2), 112-130.

[25]. रेड्डी, जी. (2018). विशेष शिक्षक: भूमिका और जिम्मेदारियाँ. *विशेष शिक्षा जर्नल*, 23(1), 45-63.

[26]. वर्मा, एस. (2019). शैक्षणिक मनोविज्ञान और समावेशी शिक्षा. *मनोवैज्ञानिक अध्ययन*, 31(4), 234-251.

[27]. वर्मा, ए. (2021). मीडिया और समावेशिता: सामाजिक दृष्टिकोण बदलना. *मीडिया अध्ययन जर्नल*, 13(2), 78-95.

[28]. वर्मा, पी., और राजपूत, एस. (2020). समावेशी शिक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका. *सामाजिक कार्य जर्नल*, 19(3), 156-174.

[29]. शर्मा, यू. (2015). भारत में समावेशी शिक्षा: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. *शैक्षिक इतिहास*, 42(1), 23-41.

[30]. शर्मा, आर. (2019). अभिभावक सहायता समूह और समावेशी शिक्षा. *पारिवारिक सहायता अध्ययन*, 11(4), 189-206.

[31]. शर्मा, ए., और पटेल, के. (2019). समावेशी शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्री का विकास. *पाठ्यक्रम अध्ययन*, 16(2), 98-115.

[32]. सक्सेना, एन., और मिश्रा, पी. (2018). शहरी-ग्रामीण विभाजन: समावेशी शिक्षा का विश्लेषण. *शहरी-ग्रामीण अध्ययन*, 26(3), 145-163.

[33]. सिन्हा, डी. (2018). भारतीय संविधान और शिक्षा का अधिकार. *संवैधानिक अध्ययन जर्नल*, 35(1), 56-74.

[34]. सिंह, आर., और कौर, जे. (2020). शिक्षकों का आत्मविश्वास और समावेशी शिक्षा. *शिक्षक मनोविज्ञान*, 15(2), 123-141.

[35]. कपूर, एम. (2019). अभिभावकों का दृष्टिकोण: समावेशी कक्षाओं में चुनौतियाँ. *अभिभावक शिक्षा जर्नल*, 12(3), 167-185.

[36]. कुमार, ए. (2020). शैक्षणिक नवाचार और समावेशिता. *नवाचार अध्ययन*, 8(1), 45-63.

[37]. खान, एस. (2020). सार्वभौमिक शिक्षण डिजाइन: सिद्धांत और अभ्यास. *शैक्षिक डिजाइन जर्नल*, 6(2), 89-107.

[38]. MHRD (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

[39]. NCERT (2019). भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा: एक सर्वेक्षण रिपोर्ट. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.

[40]. Engelbrecht, P., Nel, M., Smit, S., & Van Deventer, M. (2006). The idealism of education policies and the realities in schools: The implementation of inclusive education in South Africa. *International Journal of Inclusive Education*, 10(6), 564-580.

[41]. Kivirauma, J., Klemelä, K., & Rinne, R. (2006). Segregation, integration, inclusion–the ideology and reality in Finland. *European Journal of Special Needs Education*, 21(2), 117-133.

[42]. Mendes, E. G. (2010). Inclusive education in Brazil: Challenges and perspectives. In *Proceedings of the International Conference on Education* (pp. 234-248).

[43]. Norwich, B. (2014). Recognising value tensions that underlie problems in inclusive education. *Cambridge Journal of Education*, 44(4), 495-510.

Cite this Article:

डॉ भावना सिंह, "भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा: वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और समाधान", ***International Journal of Emerging Voices in Education,*** *ISSN: 3107-958X (Online), Volume 1, Issue 4, pp. 36-42, December 2025.*

Journal URL: *https://ijeve.com/*

DOI: *https://doi.org/10.59828/ijeve.v1i4.21*